

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क0 286/59/18/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/03/2018

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, एवं ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का पत्र क्र. 244/59/18/ब-1/चार, दिनांक 23/02/2018.

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नांकित प्रमुख विभागों के पूंजीगत व्यय को सीमित किया गया था। उक्त सीमा को पुनरीक्षित करते हुए (पुनरीक्षित अनुमान अनुसार) निम्न तालिका अनुसार नवीन सीमा निर्धारित की जाती है :-

स.क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा (राशि करोड़ रु.में)
1	2	3	4	5
1	नर्मदा घाटी विकास	48	4700	2416
2	जल संसाधन	23,45	4700,4701,4702,4705	5226
3	लोक निर्माण	24,67	4059,5054,4216	6267
4	लोक स्वा.यांत्रिकी	20	4215	1267
5	ऊर्जा (उदय योजना छोड़कर)	12	4801	3040
6	ग्रामीण विकास	30	4515	2695

2. इससे पूर्व वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 335 /आर-1133 /2009/ ब-1/चार दिनांक 30.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास हेतु (स्थापना व्यय को छोड़कर) आवंटित बजट के अधिकतम 30 प्रतिशत के व्यय की व्यय सीमा निर्धारित की गई थी ।

निरन्तर.....

//2//

3. कण्डिका-1 की तालिका के कॉलम नं. 5 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए व्यय करने पर कण्डिका-2 की सीमा (चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय) लागू नहीं होगी ।
4. राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एल 1-10/1157/2017/ब-7/डीएमसी /चार, दिनांक 09/10/2017 यथावत लागू रहेगा ।



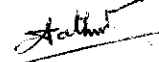
(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0287/59/18/ब-1/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/03/2018

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।



(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग